चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

बिजली चली गयी
1800–345–1111

रजि.न.34300/80 | संख्या 207 | श्री विजय पुरम, सोमवार , 03 अगस्त 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

माननीय प्रधानमंत्री ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत की

हमें हर युवा को नशे के जाल में फंसने से बचाना होगा : माननीय प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 2 अगस्त। (प.सू.का.)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। एक विशाल राष्ट्रव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े एक करोड़ से अधिक युवाओं सहित विविध सभा का औपचारिक रूप से अभिवादन किया। इस क्षण के सामूहिक महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने इस सभा को एक गहन राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने कहा, ''आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं।''

इस पहल की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिवारों, समाज और पूरे राष्ट्र के व्यापक हितों की भी पूर्ति करता है। 'नशामुक्त भारत संकल्प अभियान' के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर युवा पीढ़ी का होना अनिवार्य है, जो आत्म–विनाशकारी आदतों से पूरी तरह मुक्त हो। श्री मोदी ने कहा, ''आज जब राष्ट्र ने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो यह आवश्यक है कि देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हों और नशीले पदार्थों जैसी विनाशकारी आदतों से हमेशा के लिए दूर रहें।''

अभियान की शुरुआत पर विचार करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर गहरी संतुष्टि व्यक्त की कि यह पहल पिछले वर्ष काशी की पवित्र भूमि से एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू हुई थी। उन्होंने इस आंदोलन को संचालित करने वाली वैज्ञानिक स्पष्टता, आध्यात्मिक ऊर्जा और गहन सांस्कृतिक समर्पण के अनूठे मिश्रण पर प्रकाश डालते हुए इसके व्यापक विस्तार का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा, ''काशी घोषणा के तहत 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों और कई गैर सरकारी संगठनों के समर्थन से, कल्याणकारी यह विचार अब सफलतापूर्वक एक राष्ट्रीय परियोजना बन गया है।''

शेष पृष्ठ 4 पर

मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की परिव्यय वाली राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना 'समुद्र मंथन' को स्वीकृति प्रदान की

भारत की भावी हाइड्रोकार्बन क्षमता मुख्य रूप से कृष्णा–गोदावरी, कावेरी, महानदी और अण्डमान क्षेत्र जैसे गहरे और अति गहरे जल बेसिनों में है

उन्नत भूकंपीय सर्वेक्षणों से भारत की अपतटीय क्षमता का पता चलता है

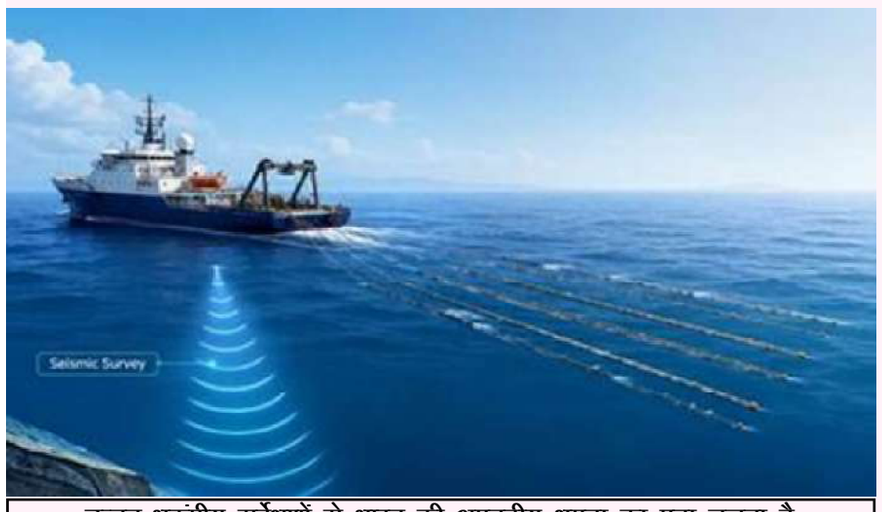

नई दिल्ली, 2 अगस्त। (प.सू.का.)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना 'समुद्र मंथन'– राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत वित्त वर्ष 2030–31 तक कार्यान्वयन के लिए 84,084 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी अपतटीय अन्वेषण अभियान है।

यह स्वीकृति भारत के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों की श्रृंखला की परिणति का प्रतीक है।

राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, समुद्र मंथन, नीति को कार्य में बदलकर और ऊर्जा सुरक्षा एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत की यात्रा में एक नया अध्याय जोड़कर इन सुधारों को आगे बढ़ाती है।

भारत कच्चे तेल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत का वार्षिक आयात बिल लगभग 144 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 13 लाख करोड़ रुपये) है। हाल के भू–राजनीतिक घटनाक्रमों से यह स्पष्ट हो गया है कि ऊर्जा संसाधनों तक सुरक्षित और निर्बाध पहुंच तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में लगातार वृद्धि होने की संभावना के साथ, आयात पर निर्भरता को कम करने, ऊर्जा मामले में लचीलापन बढ़ाने और देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सुरक्षित करने के लिए घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है।

सरकार ने 2014 से पिछले कुछ वर्षों में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण की खोज और उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई संरचनात्मक सुधार किए हैं:

अपतटीय क्षेत्र का खुलना: पहले के 99 प्रतिशत से अधिक "नो–गो" क्षेत्रों को हटा दिया गया है, जिससे भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का दस लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र पहली बार अन्वेषण के लिए उपलब्ध हुआ है।

संविदात्मक व्यवस्था का आधुनिकीकरण: भारत ने उत्पादन–साझाकरण अनुबंधों से राजस्व–साझाकरण अनुबंधों की ओर संक्रमण की ओर आगे बढ़ा है, जिससे राजकोषीय ढांचा सरल हो गया और पारदर्शिता में सुधार हुआ, साथ ही प्रशासनिक हस्तक्षेप में कमी आई है।

विधायी सुधार: तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 ने संविदात्मक स्थिरता प्रदान करके, एकीकृत पेट्रोलियम संचालन को मान्यता देकर, विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करके और एक समकालीन नियामक ढांचा स्थापित करके इस क्षेत्र पर लागू होने वाले कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण किया है।

नए नियमों के माध्यम से कार्यान्वयन: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 ने कार्य में सुगमता को बढ़ावा देकर, नियामक दक्षता में सुधार करके और पेट्रोलियम पट्टों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करके इन सुधारों को लागू किया है।

समान निर्णय लेने का ढांचा: सरकार ने सभी अनुबंध व्यवस्थाओं में सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के गठन और आदेश को भी मानकीकृत कर दिया है जिससे सभी ऑपरेटरों के लिए एकरूपता और समान अवसर सुनिश्चित हो सकें, चाहे उनके अनुबंधों पर कब हस्ताक्षर किए गए हों।

अन्वेषण पर अधिक ध्यान: ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के प्रदर्शन मापदंडों में सुधार किया गया है ताकि अन्वेषण गतिविधियों पर अधिक ज़ोर दिया जा सके। इससे भारत के घरेलू हाइड्रोकार्बन संसाधन आधार के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

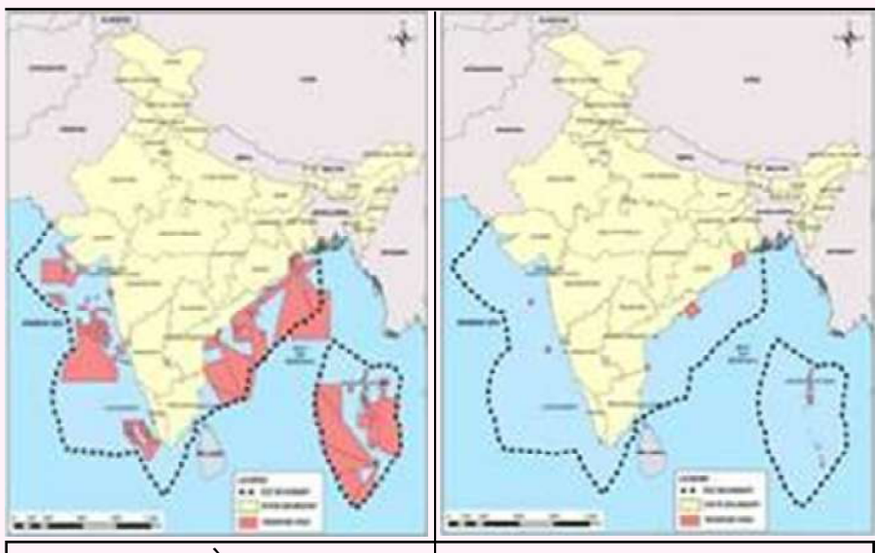

पहले	अब

पहले अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषण प्रतिबंधित था अब भारत का लगभग 99 प्रतिशत ईईज़ेड अन्वेषण के लिए खुला है

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण की पूंजीगत लागत अधिक होती है और इसमें अधिक समय लगता है। इसमें अन्वेषण ब्लॉक के आवंटन से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत तक आमतौर पर 5–10 वर्ष का समय लगता है। यह भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए निरंतर अन्वेषण की आवश्यकता को दर्शाता है।

इसके अलावा, मौजूदा तेल और गैस क्षेत्रों में प्राकृतिक उत्पादन में हर साल लगभग 6–7 प्रतिशत की कमी आ रही है, जिससे घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बनाए रखने के लिए निरंतर अन्वेषण और नई खोजें आवश्यक हो जाती हैं।

सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अन्वेषण–आधारित विकास की दिशा में अपनी नीति को पुनर्परिभाषित किया है। राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना "समुद्र मंथन" के तहत, सरकार गहरे पानी में अन्वेषण कुओं की खुदाई की लागत की 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिससे अन्वेषण जोखिम कम होगा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत की अपतटीय हाइड्रोकार्बन क्षमता के विकास में तेजी आएगी।

भारत की भावी हाइड्रोकार्बन क्षमता मुख्य रूप से कृष्णा–गोदावरी, कावेरी, महानदी और अण्डमान क्षेत्र जैसे गहरे और अति गहरे जल बेसिनों में है। इन सीमांत क्षेत्रों में अन्वेषण के

शेष पृष्ठ 4 पर

'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के अंतर्गत ज़िला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित

श्री विजय पुरम, 2 अगस्त।

राष्ट्रव्यापी 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के अंतर्गत, भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अधीन मेरा युवा भारत (माई भारत) के सहयोग से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा आज श्री विजय पुरम स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) के सभागार में ज़िला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम ने युवाओं के बीच मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर तथा उन्हें नशामुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित कर नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की मुख्य सचिव श्रीमती चंचल यादव, आईएएस, ने बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशा रोधी शपथ दिलाई तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के उन्मूलन एवं स्वस्थ तथा ज़िम्मेदार जीवनशैली को बढ़ावा देने के सामूहिक संकल्प को दोहराया।

हमारे संवाददाता के अनुसार, कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण, श्री विजय पुरम एवं आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी, माई भारत के स्वयंसेवक

तथा आमजन उपस्थित थे। राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत प्रतिभागियों ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लाइव संबोधन का भी अवलोकन किया।

यह अभियान दक्षिण अण्डमान ज़िले में उत्साहपूर्ण जनभागीदारी का साक्षी बना, जिसमें लगभग 1,000 माई भारत स्वयंसेवकों एवं युवाओं ने सहभागिता की। यह मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध युवाओं को संगठित करने तथा नशामुक्त और विकसित भारत के संदेश को सुदृढ़ करने की प्रशासन की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

CMYK

मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की परिव्यय वाली राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण

पृष्ठ 1 का शेष

लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। एक गहरे जल के अन्वेषण कुएं की लागत लगभग 125–150 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। सरकार इस प्रकार के अन्वेषण में अत्यधिक जोखिम और अत्यधिक लागत को देखते हुए निरंतर निवेश को प्रोत्साहित करने, अन्वेषण में तेजी लाने और भारत के अपतटीय हाइड्रोकार्बन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए जोखिम–साझाकरण दृष्टिकोण अपना रही है।

गहरे पानी और अत्यधिक गहरे पानी में अन्वेषण में तेजी

इसलिए समुद्र मंथन को अपतटीय अन्वेषण के जोखिम को कम करने, निजी निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और अपतटीय अन्वेषण और उत्पादन मूल्य श्रृंखला में स्थायी राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करने के लिए एक रणनीतिक राष्ट्रीय उपाय के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना "समुद्र मंथन" नीतिगत सुधारों से मिशन–आधारित कार्यान्वयन की ओर आगे बढ़ने का प्रतीक है। 31 मार्च 2031 तक 84,084 करोड़ रुपये के प्रथम चरण के परिव्यय वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में अनुमोदित यह योजना अपतटीय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है।

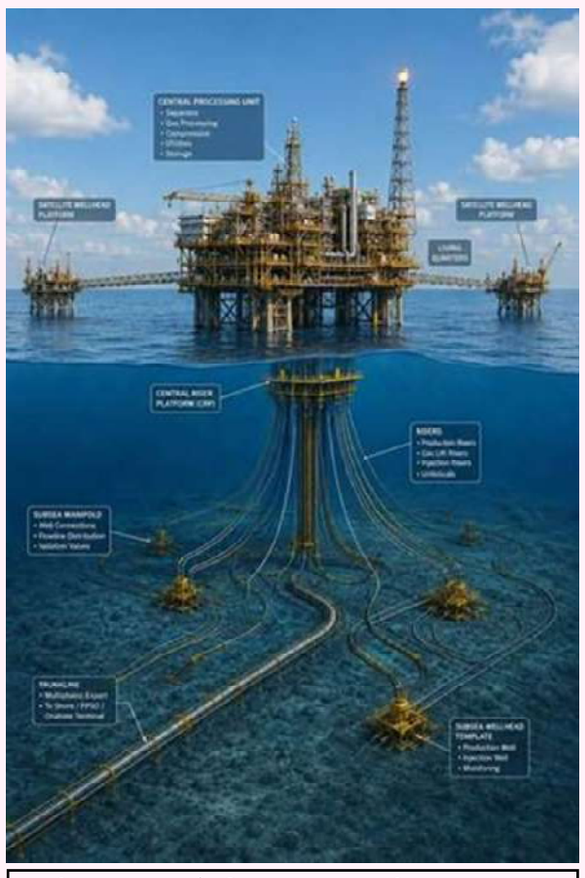

शीघ्र उत्पादन के लिए साझा अपतटीय अवसंरचना

इस योजना में चार प्रमुख घटक हैं: (1) 28,534 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले आधुनिक अपतटीय भूकंपीय डेटा का संकलन और रिकॉर्ड रखना (2) 43,200 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 60 गहरे पानी के अन्वेषण कुओं की खुदाई, जिसमें उपयुक्त खुदाई लागत के 50 प्रतिशत तक या प्रति कुआं 675 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, की सरकारी सहायता शामिल है (3) खोजों के व्यावसायीकरण को सुगम बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सामान्य अपतटीय अवसंरचना केंद्रों का विकास और (4) महत्वपूर्ण उपकरणों और सेवाओं के घरेलू विनिर्माण और स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ तेल और गैस विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की स्थापना।

क्र. सं.	घटक	राशि
1	अपतटीय डेटा संकलन	28,534
1 क	बेसिन-व्यापी कवरेज के लिए 2डी भूकंपीय डेटा संकलन	12,000
1बी	3डी भूकंपीय डेटा संकलन (और अन्य तकनीकें)	12,534
1सी	एनडीआर डेटा रीप्रोसेसिंग और एआई टूल्स का उपयोग	4,000
2	अपतटीय अन्वेषण और अवसंरचना-आधारित उत्पादन	55,200
2ए	अपतटीय अन्वेषण में तेजी लाना	43,200
2 बी	अवसंरचना आधारित गहरे पानी में उत्पादन और अन्वेषण	10,000
2सी	तेल और गैस विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास	2,000
3	निगरानी और सहायता गतिविधियां (डिजिटल उपाय, निगरानी और मूल्यांकन, मानव संसाधन, जागरूकता और प्रचार, कार्यक्रम, मीडिया)	350
	कुल	84,084

यदि अन्वेषण में सफलता मिलती है, तो राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना –समुद्र मंथन– का उद्देश्य भारत के घरेलू तेल और गैस उत्पादन को लगभग 62 एमएमटीओई से बढ़ाकर 80 एमएमटीओई प्रति वर्ष करना और देश के हाइड्रोकार्बन संसाधन आधार को 1.6 टीओई से बढ़ाकर 2.2 टीओई करना है। इस अतिरिक्त उत्पादन से कच्चे तेल के आयात में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक कमी आने की संभावना है जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

बेहतर डेटा, जोखिम साझाकरण, साझा बुनियादी ढांचे और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के माध्यम से एक मजबूत अपतटीय अन्वेषण तंत्र बनाकर, समुद्र मंथन भारत को गहरे पानी में अन्वेषण और उत्पादन में राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करने, हमारी ऊर्जा–सुरक्षा लचीलेपन को मजबूत करने और आयात पर हमारी दीर्घकालिक निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान'

पृष्ठ 1 का शेष

नशा–विरोधी शपथ लेने वाले लाखों युवाओं की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत संयम बनाए रखने और स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में नशामुक्त जीवन का संदेश सक्रिय रूप से फैलाने के उनके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। अभियान के महत्वाकांक्षी 100–सप्ताह के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे प्रत्येक आगामी रविवार को कला, संस्कृति, खेल और ध्यान से संबंधित विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि नए प्रतिभागियों को लगातार जोड़ा जा सके। श्री मोदी ने कहा, "आगामी 100 रविवार पूरी तरह से नशामुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम साबित होंगे।"

छात्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा सदस्यों और 'माई भारत' स्वयंसेवकों की विशाल ऑनलाइन सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं द्वारा प्रदर्शित गहन जागरूकता, संवेदनशीलता और गंभीर समर्पण पर अपार गर्व व्यक्त किया। युवा पीढ़ी को भारत की 'अमृत पीढ़ी' बताते हुए, उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनकी ऊर्जा, कल्पनाशीलता और प्रतिभा देश को 2047 के विकास लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा, "देश के भविष्य और आपके अपने जीवन के लिए, व्यसन से मुक्त रहना अत्यंत आवश्यक है।"

स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेल और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में आज के युवाओं की शानदार उपलब्धियों की तुलना नशीले पदार्थों के सेवन के विनाशकारी प्रभावों से करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात की कड़ी चेतावनी दी कि कैसे व्यसन एकाग्रता को भंग करता है और सपनों को चकनाचूर कर देता है। माता–पिता के सपनों को चकनाचूर करने से लेकर बुजुर्गों के लिए दैनिक पीड़ा का कारण बनने तक, परिवारों पर पड़ने वाले गहरे दुष्परिणामों को दर्शाते हुए, उन्होंने व्यापक सामाजिक प्रभाव पर ज़ोर दिया। श्री मोदी ने कहा, "जब किसी परिवार या समाज में यह विनाश होता है, तो पूरे राष्ट्र की समग्र शक्ति भी मौलिक रूप से कमज़ोर हो जाती है।"

युवाओं को नशीले पदार्थों के भ्रामक स्वभाव के प्रति आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नशीले पदार्थों से मिलने वाला क्षणिक आनंद अंततः उनके कॅरियर और पारिवारिक जीवन के लिए स्थायी पतन का कारण बनता है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक नेताओं के गहन ज्ञान, विशेष रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं का हवाला देते हुए, उन्होंने नशीले पदार्थों के प्रति समाज की ऐतिहासिक अस्वीकृति को उजागर किया। श्री मोदी ने कहा, "हमें किसी भी परिस्थिति में नशीले पदार्थों को सामाजिक स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने नशे से उबरने के लिए उपलब्ध व्यापक सहायता प्रणालियों का विस्तार से वर्णन करते हुए, व्यसन पर काबू पाने में सामाजिक सहयोग, योग, ध्यान और आधुनिक पुनर्वास केंद्रों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने परिवारों से सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधी गलत चिंताओं के बजाय चिकित्सा हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और संवेदनशील बच्चों को इस जाल में फंसने से बचाने के लिए खुले घरेलू संवाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया। श्री मोदी ने कहा, "यदि कोई युवा अनजाने में व्यसन में पड़ गया है, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उसके सभी रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हैं।"

प्रधानमंत्री ने शिक्षाविदों से विशेष अपील करते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से आग्रह किया कि वे नशीले पदार्थों के खतरों पर चर्चा को अपने नियमित पाठ्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल करें और अपने परिसरों में नशा–विरोधी अभियान चलाएं। नशे की लत से उबर रहे लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उन्होंने इन व्यक्तियों के लिए सामाजिक सम्मान और दूसरा मौका देने का आह्वान किया और उनके अतीत से जुड़ी बुराई को पूरी तरह से खारिज कर दिया। श्री मोदी ने कहा, "नशे की लत से लड़कर बाहर आने वाले युवा कमज़ोर नहीं हैं, वे असली योद्धा हैं जिनका अविश्वसनीय साहस ही उनकी सच्ची पहचान है।"

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के समापन में युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार इस महत्वपूर्ण लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कार्रवाई, हजारों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में जब्ती और नशीले पदार्थों के डीलरों और तस्करों को निशाना बनाकर की गई गिरतारियों की बढ़ती दर का हवाला दिया। युवा पीढ़ी के लचीलेपन पर अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय पहल की अत्यधिक सफलता की भविष्यवाणी की। श्री मोदी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि हमारे युवा नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा बचाएंगे और विकसित भारत के संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे।"

ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन पर मास्टर ट्रेनर क्षमता निर्माण कार्यशाला सम्पन्न

श्री विजय पुरम, 2 अगस्त।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) द्वारा, नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के सहयोग से आयोजित "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन" विषय पर दो दिवसीय केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय मास्टर ट्रेनर क्षमता निर्माण कार्यशाला का समापन 29 जुलाई को श्री विजय पुरम स्थित आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रशिक्षण सभागार में हुआ।

यह कार्यशाला भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारत–नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल (द्वितीय चरण) के अंतर्गत आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, गैर–सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य हितधारकों सहित 23 हितधारक विभागों एवं संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

एएनपीसीसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दो दिवसीय कार्यशाला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), थोक अपशिष्ट उत्पादक (बीडब्ल्यूजी) अनुपालन

तथा सतत अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों के साथ–साथ व्यावहारिक अभ्यास भी शामिल थे।

समापन सत्र में एएनपीसीसी के सदस्य सचिव–सह–निदेशक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन को केवल नियामकीय दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में भी अपनाया जाना चाहिए, विशेषकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में। उन्होंने प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों की ज़िम्मेदारी पर भी बल दिया कि वे कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाएं तथा अपने–अपने विभागों एवं संगठनों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

राजकीय पॉलिटेक्निक, डिगलीपुर में विभिन्न संविदा पदों की भर्ती परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी

श्री विजय पुरम, 2 अगस्त

राजकीय पॉलिटेक्निक, डिगलीपुर में विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए अनंतिम रूप से पात्र घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से पूर्व में अधिसूचित परीक्षा कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया गया है। परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार है:

तिथि	समय	परीक्षा	स्थल
18 अगस्त, 2026	सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक	प्रवक्ता (सिविल, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण तथा गणित) के लिए संगणक आधारित परीक्षा	संगणक आधारित परीक्षा प्रयोगशाला
19 अगस्त, 2026	सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक	प्रयोगशाला तकनीशियन (सिविल एवं कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण) के लिए संगणक आधारित परीक्षा	
20 अगस्त, 2026	सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक	प्रवक्ता एवं तकनीशियन (सिविल एवं कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण) के लिए कौशल परीक्षा	संबंधित प्रयोगशालाएं (कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण) तथा सिविल अभियंत्रण प्रयोगशालाएं

यहां प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी पूर्व में जारी प्रवेश–पत्र का ही उपयोग कर सकते हैं।

एनकॉल में आठ स्नातक (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 2 अगस्त

क्र.सं.	कार्यक्रम	तिथि
1.	4 स्नातक पाठ्यक्रमों–बी.कॉम (सामान्य), बी.कॉम (कॉरपोरेट सचिवीय), बीबीए हेतु सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग	5 अगस्त, 2026 सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक भोजनावकाश दोपहर 1.30 बजे से सायं 5 बजे तक
2.	4 स्नातक पाठ्यक्रमों–बी.ए. (अर्थशास्त्र), बी.ए. (समाजशास्त्र) तथा बी.पी.ए. संगीत (हिन्दुस्तानी गायन एवं वाद्य) हेतु सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग	6 अगस्त, 2026 सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक भोजनावकाश दोपहर 1.30 बजे से सायं 5 बजे तक

शैक्षणिक सत्र 2025–2026 के लिए अण्डमान कॉलेज (एनकॉल) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त कार्यक्रमानुसार काउंसलिंग–सह–प्रवेश प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण–पत्रों के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का एक–एक सेट साथ लाना होगा। काउंसलिंग के दिन ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वे विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, जिसमें कक्षा 12वीं के अंक एवं कुल/औसत प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित हो, तथा प्रवेश हेतु आवश्यक सभी सहायक दस्तावेज़ों के साथ काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ऐसे ऑफलाइन आवेदन उसी दिन सुबह 10.30 बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि ऑफलाइन प्रवेश मेरिट सूची तैयार की जा सके। निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग–सह–प्रवेश प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश का दावा स्वतः निरस्त माना जाएगा। अस्थायी रूप से प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उसी दिन निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। काउंसलिंग–सह–प्रवेश के समय सभी आवश्यक मूल दस्तावेज़, उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का एक–एक सेट तथा दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको) श्री विजय पुरम

सलाहकार की नियुक्ति हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू

अनिडको, भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनिडको / अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की सहायता हेतु सलाहकारों की नियुक्ति प्रस्तावित करता है। इन पदों हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा अन्य नियम एवं शर्तों का विवरण वेबसाइट https://andamannicobar.gov.in तथा https://aniidco.and.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 12/08/2026 तक महाप्रबंधक (कार्मिक), अनिडको लिमिटेड, विकास भवन, श्री विजय पुरम–744101 के पते पर भेज सकते हैं अथवा ई–मेल aniidco@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

वॉक–इन–इंटरव्यू दिनांक 17/08/2026 को व्यक्तिगत रूप से या गूगल मीट (VC) के ज़रिए होगा। गूगल मीट (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) का लिंक उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड किया जा सकता है।

निगम को किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

अधिक जानकारी के लिए aniidco@gmail.com, 03192–231193 पर संपर्क करें:

महाप्रबंधक (कार्मिक), अनिडको

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको), श्री विजय पुरम

रेजिडेंट इंजीनियर–सह–समन्वयक, सर्वेयर–सह–जीआईएस विशेषज्ञ एवं सलाहकार (परियोजना अनुश्रवण एवं अनुवर्ती कार्य) की नियुक्ति के लिए वॉक–इन–इंटरव्यू

अनिडको भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनिडको / अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की सहायता हेतु रेजिडेंट इंजीनियर–सह–समन्वयक, सर्वेयर–सह–जीआईएस विशेषज्ञ एवं सलाहकार (परियोजना अनुश्रवण एवं अनुवर्ती कार्य) के पदों पर योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रस्तावित करता है। इन पदों हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा अन्य नियम एवं शर्तों का विवरण वेबसाइट https://andamannicobar.gov.in तथा https://aniidco.and.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 17/08/2026 तक महाप्रबंधक (कार्मिक), अनिडको लिमिटेड, विकास भवन, श्री विजय पुरम – 744101 के पते पर भेज सकते हैं अथवा ई–मेल aniidco@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। वॉक–इन–इंटरव्यू का आयोजन दिनांक 19/08/2026 को किया जाएगा।

निगम को किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

अधिक जानकारी के लिए aniidco@gmail.com, 03192.231193 पर संपर्क करे।

महाप्रबंधक (कार्मिक), अनिडको

शपथ पत्र

मैं, श्रीमती दीलैला पत्नी मिस्टर इरासमस निवासी मकान संख्या 72, किनयूका ग्राम, कार निकोबार तहसील, निकोबार जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करती हूँ :

1. कि मैं मिसी कार्टसन की माता हूँ।
2. कि मेरा नाम दीलैला मेरे सभी सरकारी अभिलेखों और दस्तावेजों में सही दर्ज किया गया है।
3. कि मेरे बेटे मिसी कार्टसन के माध्यमिक स्कूल (दसवीं पास) के प्रमाणपत्र में गलती से दीलैला के स्थान पर दिलैला दर्ज किया गया है।
4. कि दीलैला और दिलैला नाम एक ही समान व्यक्ति के है जो मेरा नाम है।
5. कि यह शपथ पत्र यह घोषित करने के लिए किया गया है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है साथ ही आम जनता और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे पासपोर्ट जारी करने और अन्य सरकारी रिकार्ड सहित सभी कानूनी और अधिकारिक कार्यों के लिए दीलैला और दिलैला को एक ही व्यक्ति माने।

कि इस शपथ पत्र के कथन मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

Rescheduling of Examination

F No.DBRAIT/01-2026/005 Dated : 01/08/2026

This is to inform all candidates who are provisionally eligible for recruitment to various contractual posts at Government Polytechnic, Diglipur that, due to administrative reasons, the examination schedule notified earlier has been rescheduled. The revised schedule of examination is as follows:

Date	Time	Exam	Venue
18/8/2026	10am – 12noon	CBT for lecturer (Civil, CSE, Maths	CBT Lab
19/8/2026	10am – 12noon	CBT for Lab Technician(Civil & CSE)	
20/8/2026 onwards	9am – 6pm	Skill Test for Lecturer & Technician (Civil & CSE)	Respective labs (CSE) and Civil Engg. Labs

Candidates may retain the previous hall ticket. Note that exam attendance does not guarantee selection; final appointment is subject to meeting all eligibility criteria as per the Recruitment Rules (RR).

Chairman
(Recruitment Committee-GPD)

दिल्ली में 5 अगस्त को 'जीआई एंड बियॉन्ड 2.0' शिखर सम्मेलन

नई दिल्ली, 02 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 5 अगस्त को 'जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा करेंगे।

वस्त्र मंत्रालय के अनुसार हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के हीरक जुबली लोगो का औपचारिक अनावरण और डिजिटल हैंडलूम एटलस "एक मंच, अनंत बाजार" का शुभारंभ किया जाएगा। विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के जीआई–टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देना तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी पहुंच को मजबूत करना है।

इस दिन देश भर से 100 से अधिक जीआई–पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए एक मंच, अनंत बाजार टैगलाइन के साथ एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के हीरक जुबली लोगो का औपचारिक अनावरण होगा। पंजीकृत मालिकों और नए अधिकृत उपयोगकर्ताओं को जीआई प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। जीआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी।

इसके अलावा, 10 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार, देश भर के निर्यातक, प्रमुख कपड़ा ब्रांड्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म और नीति निर्माता एक साथ आएंगे। जीआई पंजीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकार, घरेलू बाजार में जीआई उत्पादों का प्रचार–प्रसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जीआई हथकरघा उत्पादों के लाभ उठाने की रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार–विमर्श किया जाएगा।

वैश्विक सुधार रैंकिंग में भारत 57वें स्थान पर पहुंचा

नई दिल्ली, 02 अगस्त। भारत संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा–समर्थक सुधारों की वैश्विक रैंकिंग में 25 स्थान ऊपर चढ़कर 82वें से 57वें स्थान पर पहुंच गया है। कॉम्पिटर फाउंडेशन द्वारा जारी इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर: रिड्यूसिंग एंटी–कॉम्पिटिटिव मार्केट डिस्टॉर्शंस टू बिल्ड ऑन इंडियाज 2010–2023 रिफॉर्म प्रोग्रेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट 2010 और 2023 के बीच देश के सुधार पथ की जांच करते हुए, अपने बाजार विकृति प्रदर्शन सूचकांक के तहत भारत के प्रदर्शन का आकलन करती है, और बाजार विकृतियों को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में निरंतर प्रयासों में सुधार का श्रेय देती है। रिपोर्ट तीन व्यापक स्तंभों– संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, घरेलू प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बाजार की विकृतियों का मूल्यांकन करती है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आई बी सी), नियामकीय वातावरण में सुधार और व्यापार सुविधा प्रणाली के आधुनिकीकरण जैसे सुधारों पर प्रकाश डाला गया है।

सीडब्ल्यूजी 2026: एक दिन में 16 मेडल जीतकर भारत ने लगाई मेडल टैली में लंबी छलांग, चौथे स्थान पर काबिज

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए 10वां दिन ऐतिहासिक रहा। देश ने बॉक्सिंग में 10 मेडल समेत कुल 16 मेडल अपने नाम किए। एथलीटों के दमदार प्रदर्शन के बूते भारत ने मेडल टैली में भी लंबी छलांग लगाई है।

भारत अब 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ मेडल टैली में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत के कुल मेडल की संख्या अब 39 हो गई है और देश ने छह पायदान की छलांग लगाई है। ऑस्ट्रेलिया 10वें दिन भी अपनी बादशाहत को बरकरार रखने में सफल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास 61 गोल्ड, 38 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल हैं।

इंग्लैंड 25 गोल्ड, 40 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल लेकर कुल 99 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं, कनाडा 18 गोल्ड समेत 57 मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर काबिज है। भारत के शानदार प्रदर्शन के कारण मेजबान स्कॉटलैंड अब पांचवें नंबर पर खिसक गया है। स्कॉटलैंड के 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वहीं, नाइजीरिया 10 गोल्ड समेत कुल 21 मेडल जीतकर छठे नंबर पर मौजूद है। वेल्स 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल लेकर सातवें स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड 8 गोल्ड के साथ कुल 27 मेडल जीतकर आठवें नंबर पर मौजूद है।

10वें दिन भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन लाजवाब रहा। खासतौर पर भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए कुल 10 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 7 गोल्ड शामिल रहे। पुरुष कैटेगरी में अंकुश पंघाल और सचिन सिवाच ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि महिला कैटेगरी में जैस्मिन लैम्बोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस, अरुंधति चौधरी और प्रीति ने गोल्डन पंच लगाया। वहीं, जदुमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं, ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर, जबकि सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं, शॉट पुट में भी भारत का प्रदर्शन दमदार रहा। सोमन राणा ने गोल्ड, जबकि शुभम जुयाल ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया।–आईएएनएस

आजादी के 79 वर्ष पूरे होने पर एनसीसी ने आयोजित किया साइक्लोथॉन–2026

नई दिल्ली, 02 अगस्त।। नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) ने भारत की आजादी के 79 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में साइक्लोथॉन–2026 का आयोजन किया। 'स्वच्छ भारत, हरित भारत, फिट भारत' थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली के लिए प्रेरित करना था। इसके साथ ही देशभक्ति, अनुशासन, एकता और राष्ट्र सेवा जैसे मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया गया।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, प्रख्यात मुक्केबाज एम.सी. मैरी कॉम और विख्यात टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भी मौजूद रहे।

भारत की आजादी के 79 वर्ष पूरे होने के प्रतीक के तौर पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने 79 एनसीसी कैडेटों के दल के साथ 79 किलोमीटर की सांकेतिक साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया। साइक्लोथॉन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू हुआ और राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए निर्धारित मार्ग पूरा करने के बाद वहीं संपन्न हुआ।

साइक्लोथॉन के जरिए एनसीसी ने 'टीबी मुक्त भारत', 'स्वच्छ भारत', 'एक पेड़ माँ के नाम' और 'हर घर तिरंगा' जैसे राष्ट्रीय अभियानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों और आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

आयोजन के दौरान साइकिल को पर्यावरण–अनुकूल, टिकाऊ और प्रभावी परिवहन साधन के रूप में अपनाने का संदेश दिया गया। इसके जरिए युवाओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

एनसीसी साइक्लोथॉन–2026 केवल खेल गतिविधि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शारीरिक फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जन–जागरूकता का मंच भी बना। इस पहल के जरिए

युवाओं को अनुशासन, टीम भावना, धैर्य और सामुदायिक सेवा की भावना के साथ सकारात्मक सामाजिक बदलाव का वाहक बनने का संदेश दिया गया।

एनसीसी की इस पहल ने युवाओं को स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। आयोजन ने सशक्त, स्वस्थ और हरित भारत के निर्माण के संकल्प को भी नई ऊर्जा प्रदान की। (इनपुटः पीआईबी)

ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में होगी

नई दिल्ली, 02 अगस्त। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की दो दिन की बैठक कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली यह बैठक 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण' के व्यापक विषय पर आधारित है।

ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।

बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है।

चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धिः सफदरजंग अस्पताल में हुई दुनिया की पहली रोबोटिक एवी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। नई दिल्ली स्थित वीएमएमसी (वीएमएमसी) और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार एक बेहद दुर्लभ जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित वयस्क मरीज का रोबोटिक तकनीक से सफल ऑपरेशन किया है। इस उपलब्धि को वैश्विक चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता शर्मा के नेतृत्व में कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग की टीम ने यह जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। ऑपरेशन का नेतृत्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) अनुभव गुप्ता ने किया। खास बात यह है कि इस तरह की रोबोटिक सर्जरी दुनिया में पहली बार की गई है और इससे भारत का नाम वैश्विक चिकित्सा क्षेत्र में और मजबूत हुआ है।

जिस मरीज का ऑपरेशन किया गया, वह दो बेहद दुर्लभ जन्मजात हृदय समस्याओं से जूझ रहा था। पहली बीमारी थी कंजेनिटली करेक्टेड ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज (सीसीटीजीए), जिसमें हृदय के निचले कक्ष सामान्य स्थिति से उल्टे होते हैं। इस वजह से हृदय के दाहिने हिस्से को पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने का अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ता है। दूसरी समस्या डेक्स्ट्रोकार्डिया थी, जिसमें दिल सामान्य बाईं ओर होने के बजाय दाईं ओर स्थित होता है। इन दोनों स्थितियों के कारण मरीज के हृदय का एवी वाल्व गंभीर रूप से खराब हो चुका था और हृदय की कार्यक्षमता भी लगातार कम होती जा रही थी।

आमतौर पर रोबोटिक हार्ट सर्जरी छाती के दाईं ओर से की जाती है, लेकिन इस मरीज का दिल दाईं तरफ होने के कारण डॉक्टरों ने पूरी तकनीक को बदलते हुए बाईं ओर से रोबोटिक सर्जरी की। यह तरीका पूरी तरह नया था और मेडिकल इतिहास में पहली बार अपनाया गया।

सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने छाती की हड्डी काटने के बजाय छोटे–छोटे छिद्रों के जरिए रोबोटिक उपकरणों और हाई–डेफिनिशन 3डी विजुअल सिस्टम का इस्तेमाल किया। इससे बेहद सटीक तरीके से वाल्व को बदला गया और ऑपरेशन सफल रहा।

इस आधुनिक तकनीक के कई फायदे हैं। मरीज की छाती की हड्डी नहीं काटनी पड़ती, जिससे दर्द कम होता है। खून का नुकसान भी बहुत कम होता है और संक्रमण का खतरा घट जाता है। इसके अलावा मरीज पहले की तुलना में काफी जल्दी स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि केवल एक सफल सर्जरी नहीं, बल्कि भारत के सरकारी अस्पतालों की बढ़ती क्षमता और आधुनिक चिकित्सा तकनीक का प्रमाण है। इससे यह भी साबित हुआ है कि देश के सरकारी संस्थानों में विश्वस्तरीय इलाज और अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह ऐतिहासिक सफलता आने वाले समय में जटिल हृदय रोगों के इलाज के लिए नई राह खोलेगी। साथ ही दुनिया भर के सर्जनों के लिए यह एक नई तकनीक और शोध का आधार भी बनेगी।–आईएएनएस

ताइपे ओपन का खिताब जीतकर 17 वर्षीय तन्वी शर्मा बनीं चैंपियन, रचा इतिहास

ताइपे, 2 अगस्त (आईएएनएस)। 17 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस खिताब को जीतने वाली किसी भी कैटेगरी की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी हैं। यह उनका पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल भी है।

तन्वी ने रविवार को महिला सिंगल्स फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुयेन थुई लिन्ह को 21–16, 21–16 से हराकर शानदार जीत हासिल की। वह साइना नेहवाल (2008) के बाद ताइपे ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी बन गई हैं। जीत के साथ ही इस टूर्नामेंट में भारत का 17 साल का खिताबी सूखा खत्म हो गया है। 2009 में टूर्नामेंट के ग्रां प्री गोल्ड दौर में ज्वाला गुट्टा और वी. दिजु की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी की जीत के बाद यह देश की कुल तीसरी जीत है।

शुरुआती गेम में तन्वी ने तेजी से अपना दबदबा बनाया और 10–2 की बढ़त हासिल कर ली, हालांकि गुयेन ने अंतर को कम करके 10–8 कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए आसानी से पहला गेम 21–16 से जीत लिया।

इस जीत के साथ वह सुपर 300 या उससे ऊंचे स्तर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला सिंगल्स शटलर बन गई हैं और साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और देविका सिहाग के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गईं। अपने शानदार प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए तन्वी ने कहा, यह खिताब जीतकर मैं बहुत खुश हूं। मैंने हर कदम और हर मैच पर ध्यान देते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की और मुझे लगा कि पूरे टूर्नामेंट में मैंने बहुत अच्छा खेला। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मैंने खुद से कहा कि अपना 100 प्रतिशत दूं और अपने खेल पर ध्यान बनाए रखूं।

तन्वी के युवा करियर का यह केवल दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल मुकाबला था। इससे पहले, यूएस ओपन में बेइवेन झांग से हारकर वह उपविजेता रही थीं। 17 साल और 222 दिन की उम्र में, वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट भी बनीं। उन्होंने कोरियाई डबल्स दिग्गज ली योंग डे का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2006 में पुरुषों के डबल्स खिताबी मुकाबले में पहुंचने के समय 17 साल और 287 दिन के थे।–आईएएनएस

क्या आपको 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना जरूरी था? जानिए किन टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होती यह डेडलाइन

नई दिल्ली, 02 अगस्त (आईएएनएस)। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा खत्म हो चुकी है और अंतिम दिन बड़ी संख्या में करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया। हालांकि, हर टैक्सपेयर के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख नहीं थी। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि इस बात पर निर्भर करती है कि करदाता की आय का स्रोत क्या है और उसे कौन–सा आईटीआर फॉर्म भरना है।

आयकर विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष (एवाई) 2026–27 के लिए 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इनमें से 40 लाख से ज्यादा रिटर्न केवल अंतिम दिन दाखिल हुए। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करदाताओं का समय पर टैक्स अनुपालन करने के लिए आभार जताते हुए कहा कि उनका सहयोग देश की आर्थिक प्रगति को गति देता है।

लेकिन जिन व्यक्तियों की आय व्यवसाय (बिजनेस) या पेशे से होती है और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट आवश्यक नहीं है, उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। इस श्रेणी में फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, छोटे कारोबारी और कई प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जो सामान्यतः आईटीआर–3 या आईटीआर–4 फॉर्म भरते हैं।

वहीं, यदि किसी व्यवसाय या पेशे से जुड़े करदाता के खातों का टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, तो उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे करदाताओं को 31 जुलाई की डेडलाइन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

यदि आपकी आय केवल वेतन, पेंशन, ब्याज, किराया या पूंजीगत लाभ से है, तो सामान्यतः 31 जुलाई की समयसीमा लागू होती है। वहीं, यदि आपकी आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है, तो आपकी डेडलाइन 31 अगस्त या 31 अक्टूबर हो सकती है। इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके लिए कौन–सी समय सीमा लागू है।

आमतौर पर, अगर किसी व्यक्ति की कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो उसे आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होता है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपए, 60 से 79 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपए और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए है।

हालांकि, कुछ मामलों में आय छूट सीमा से कम होने के बावजूद भी आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। यदि किसी निवासी भारतीय के पास विदेश में कोई संपत्ति है, वह किसी विदेशी संपत्ति का लाभार्थी है, किसी विदेशी बैंक खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है या विदेश में कोई वित्तीय हित रखता है, तो उसे अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होगा।

इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित हाई–वैल्यू वित्तीय लेनदेन किए हैं या उसकी कुल आय कटौतियों और छूट (जैसे धारा 80सी से 80यू या धारा 54 आदि) का लाभ लेने से पहले मूल छूट सीमा से अधिक है, तब भी आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, आकलन वर्ष 2026–27 के लिए 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। अंतिम दिन 40 लाख से ज्यादा करदाताओं ने रिटर्न फाइल किया, जिससे साफ है कि बड़ी संख्या में लोगों ने आखिरी समय तक इंतजार किया। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने और कर नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि अनावश्यक जुर्माने और ब्याज से बचा जा सके। –आईएएनएस

पीएम विश्वकर्मा योजना से 24 लाख से अधिक कारीगरों को मिला लाभ, कौशल और आय में हुआ सुधार

नई दिल्ली, 02 अगस्त।

केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देशभर के 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन, ऋण सहायता, आधुनिक उपकरण, डिजिटल प्रोत्साहन और विपणन सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के अनुसार, अब तक 24.29 लाख से अधिक लाभार्थी बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और योजना से उनकी आय तथा रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी। योजना का उद्देश्य अपने हाथों और पारंपरिक औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करना है। इनमें बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, धातु शिल्पकार, टूल किट निर्माता, ताला निर्माता, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार एवं पत्थर शिल्पकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक खिलौना निर्माता, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी तथा मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले कारीगर शामिल हैं।

सरकार ने बताया कि आईआईएम मुंबई द्वारा किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना के समवर्ती मूल्यांकन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 11,591 लाभार्थियों तथा बैंक अधिकारियों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), इंडिया पोस्ट कर्मियों और प्रशिक्षण केंद्रों सहित विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया शामिल की गई। अध्ययन के अनुसार, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 93ः लाभार्थियों ने अपनी आय में सामान्य से लेकर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कौशल प्रशिक्षण से उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला।

सरकार के अनुसार, सफलतापूर्वक पंजीकृत लाभार्थियों को तीन स्तरों की जांच के बाद योजना के सभी लाभ प्रदान किए जाते हैं। इनमें कौशल उन्नयन, ऋण सहायता, आधुनिक टूलकिट, डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा, विपणन सहयोग और उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण शामिल हैं। लाभार्थियों को आधुनिक उपकरणों, नवीन डिजाइनों, बेहतर कार्य–पद्धतियों और व्यवसाय विस्तार से संबंधित जानकारी भी दी जाती है।

योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर भी किया जाता है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण, व्यवसाय विस्तार, उपकरणों के आधुनिकीकरण और औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के अवसर मिलते हैं। सरकार का कहना है कि इससे कारीगर आत्मनिर्भर बनने के साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

यह जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक कौशल, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। (इनपुट– पीआईबी)

दिल्ली में 5 अगस्त को 'कपड़े के भीतर की दुनियाः बुनाई के नए क्रम' प्रदर्शनी का होगा उद्घाटन

नई दिल्ली, 02 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में 5 अगस्त को 14 दिवसीय कपड़े के भीतर की दुनियाः बुनाई के नए तरीके नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार इसका उद्घाटन सचिव नीलम शमी राव करेंगी। यह प्रदर्शनी विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा 7 अगस्त को मनाए जाने वाले '12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के देशव्यापी समारोहों के एक प्रमुख हिस्से के रूप में आयोजित की जाएगी। श्रेयांसि सिंह द्वारा क्यूरेट की गई यह प्रदर्शनी समकालीन वस्त्र कलाकारों, डिजाइनरों और शिल्प समूहों को एक साझा मंच प्रदान करती है।प्रदर्शनी में शोध–आधारित कार्यों, कलाकार–कारीगर सहयोग और आकर्षक इन्स्टॉलेशन के माध्यम से वस्त्र निर्माण के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में आद्यम हैंडवॉवन, अब्राहम एंड थाकोर, आस्था बुटैल, बोइटो, चाणक्य स्कूल, कुन्नूर एंड कंपनी, जागृति फुकन, जयिता चटर्जी, कार्दो, मोरी, नीरज पटेल, पोरगई आर्टिसन्स एसोसिएशन, श्रद्धा कोचर, श्रुजन, स्टूडियो मीडियम, उज्ज्वल डे और 23 एन 69 ई जैसे जाने–माने कलाकारों व संस्थानों की कृतियाँ देखने को मिलेंगी।

आयुष हेल्थ इंश्योरेंस को विस्तार देने के लिए सरकार ने बनाई नई व्यवस्था

नई दिल्ली, 02 अगस्त।

केंद्र सरकार ने आयुष उपचारों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में व्यापक रूप से शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने बताया कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के तहत बीमा कंपनियों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सहित सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अन्य चिकित्सा प्रणालियों के समान बीमा कवरेज प्रदान करना होगा।

सरकार के अनुसार, 29 मई 2024 को जारी IRDAI मास्टर सर्कुलर के तहत बीमा कंपनियों को ऐसे उत्पाद, ऐड–ऑन और राइडर उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें आयुष उपचार भी शामिल हों। साथ ही कंपनियों को बोर्ड से अनुमोदित अंडरराइटिंग नीति अपनानी होगी, ताकि पॉलिसी धारकों को अपनी पसंद की चिकित्सा पद्धति चुनने का विकल्प मिल सके।

स्वास्थ्य बीमा में आयुष उपचारों की पारदर्शिता और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2026 में आयुष उपचारों के लिए बीमा कवरेज की बेंचमार्क दरों को संशोधित किया है। इसमें मानकीकृत उपचार पैकेज, अतिरिक्त प्रक्रियाएं और संचालन संबंधी दिशा–निर्देश शामिल किए गए हैं।

मंत्रालय ने देशभर में आयुष उपचारों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से पांच जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में बीमा कंपनियों और आयुष संस्थानों को ROHINI (Registry of Hospitals in Network of Insurance) में पंजीकरण, बीमा कंपनियों के साथ सूचीबद्ध होने, डिजिटल दस्तावेजीकरण और क्लेम प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

आयुष मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के बीच एक समझौता ज्ञापन भी कराया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के सरकारी आयुष अस्पतालों को एक साझा व्यवस्था के तहत बीमा कंपनियों के नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि बीमा धारकों को आयुष उपचार आसानी से उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा, आयुष स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए AIIA, नई दिल्ली में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित की गई है। यह इकाई आयुष अस्पतालों के सूचीबद्धीकरण, बीमा कंपनियों के साथ समन्वय, शिकायत निवारण और आयुष स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करेगी।–पीआईबी

प्रोटीन के मामले में अंडे से बेहतर हो सकते हैं ये ऑप्शंस, जो देंगे बॉडी को फौलादी ताकत

नई दिल्ली, 02 अगस्त।।

स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि इसकी कमी से कमजोरी, थकान और शरीर में दर्द होने लगती है। ऐसे में मसल्स और हड्डियों को मजबूत करने के लिए लोग प्रोटीन से भरपूर चीजों को खाने की सलाह देते है।

आपको बता दें, कुछ लोग प्रोटीन के लिए अंडा खाने की सलाह देते हैं, लेकिन कई लोग अंडा खाने से परहेज भी करते है। अगर आप भी इन्ही लोगों में शामिल है तो आज हम आपको अंडे की बजाय कुछ 5 चीजों को खाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से आप शरीर में हुई प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते है। इन चीजों में अंडे से अधिक प्रोटीन होता है। आप इन चीजों को अपनी हाइट का हिस्सा बना सकते है।

जैसा कि आप जानते है कि दालें प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत हैं, खासकर शाकाहारी लोगों के लिए, और कई प्रकार की दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं, जैसे कि मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल, लोबिया आप इन सभी दालों को प्रोटीन के लिए खा सकते है। इन सभी दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है।

आपको बता दें, पनीर में भी खूब प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 11–14 ग्राम तक प्रोटीन होता है। शाकाहारी लोगों के लिए पनीर एक अच्छा ऑप्शन है। पनीर खाने से कैल्शियम और विटामिन बी12 मिलता है जो सेहत के लिए जरूरी है।

प्रोटीन के लिए आपको सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। बता दें, 100 ग्राम उबले हुए सोयाबीन में करीब 16.6 ग्राम प्रोटीन होता है इसे खाने से अंडे से कई ज्यादा प्रोटीन मिलता है। अगर आप शाकाहारी है तो प्रोटीन के लिए सोयाबीन का सेवन कर सकते है।

एक्सपर्ट्स की मानें तो, मशरूम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आप मशरूम को खा सकते हैं आपको बता दें कि, 100 ग्राम तक मशरूम में लगभग 3–4 ग्राम प्रोटीन होता है। ब्रोकली का सेवन प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते है। बता दें, 100 ग्राम ब्रोकली में लगभग 2.8 ग्राम प्रोटीन होता है। आप ब्रोकली को कच्चा सलाद के तौर पर या उबालकर खा सकते है।

3000 हाथियों की मदद और 80 टन के पत्थर का कमाल! आखिर कैसे बिना सीमेंट–लोहे के 1000 सालों से खड़ा है यह मंदिर?

नई दिल्ली, 02 अगस्त।

क्या आप जानते हैं देश की उस ऐतिहासिक इमारत के बारे में जिस बनाने के लिए न तो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया और न ही लोहे का, इसके बावजूद 1000 सालों से यह मजबूती से खड़ी हुई है? सदियों से आंधी–तूफान और भूकंप जैसी आपदा झेलने वाली यह ऐतिहासिक इमारत धार्मिक महत्व भी उतना ही रखती है। हम बात कर रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर की।

दक्षिण भारत की द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बहतरीन उदाहरण बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इस मंदिर को राजराजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो साल 1010 ई. में राजराज चोल प्रथम ने इसे बनवाया था। माना जाता है कि बृहदेश्वर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है।

बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ी खास बातें

मंदिर को बनाने में करीब 1.3 लाख वजन के ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है।

इसकी 13 मंजिलों का गर्भ गृह बनाने के लिए 3000 से ज्यादा हाथियों की मदद ली गई थी।

पत्थरों को जोड़ने के लिए कैमिकल, सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बजाय पत्थरों के खांचों को आपस में फंसाकर इस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया था।

मंदिर का शिखर करीब 216 फीट ऊंचा है, जिसपर 80 टन से ज्यादा वजन वाले पत्थर से बना एक कुंभम भी लगा हुआ है।

द्रविड़ वास्तुकला में बने इस मंदिर में देवी–देवताओं और खूबसूरत मूर्तियों की नक्काशी की गई है।

भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका बिना किसी नींव के खड़ा होना है। मंदिर का दूसरा रहस्य यह कि इसके शिखर पर जो कुंभम लगाया गया था, वह एक ही पत्थर से बना था। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थर को कैसे लगाया गया होगा? कहा तो यह भी जाता है कि इस कुंभम की कोई परछाई नहीं बनती, यह साइंस इस बात को केवल मिथक करार देता है।

साइंस का मानना है कि क्योंकि यह मंदिर पिरामिड आकार में बना है, इसका निचला हिस्सा चौड़ा और ऊपरी हिस्सा चौड़ाई में बहुत कम है। इसी वजह से कुंभम की परछाई अपने ही आधार पर बनती है और नीचे दिखाई नहीं देती। इन सबके बावजूद भी यह सच नहीं बदलने वाला कि उस समय के शिल्पकार और उनकी इंजीनियरिंग कितनी महान थी।

राष्ट्रीय अंगदान दिवसः एक फैसला, जो दे सकता है कई जिंदगियों को नया जीवन

नई दिल्ली, 02 अगस्त।

हमारे देश में हर साल 3 अगस्त को 'राष्ट्रीय अंगदान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस महादान के लिए प्रेरित करना है। जीवन देना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन किसी बुझते हुए जीवन को नई उम्मीद देना इंसानियत का सबसे बड़ा कर्तव्य है। भारत में हर साल लाखों मरीज सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर किडनी, लीवर, हृदय या आंखें जैसे आवश्यक अंग नहीं मिल पाते। अंगों की मांग और आपूर्ति के बीच का यह अंतर केवल जागरूकता की कमी के कारण है।

अंगदान को लेकर समाज में फैली अज्ञानता और कई तरह के भ्रम इसकी सबसे बड़ी बाधा हैं। कई लोग सोचते हैं कि केवल युवा लोग ही अंगदान कर सकते हैं या धर्म अंगदान की अनुमति नहीं देता। जबकि सच्चाई यह है कि अंगदान में उम्र कोई बाधा नहीं होती और दुनिया का हर मुख्य धर्म किसी की जान बचाने को सबसे बड़ा पुण्य मानता है। जब किसी व्यक्ति को डॉक्टरों द्वारा ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है, तब सही समय पर किया गया अंगदान 8 अलग–अलग लोगों को नया जीवन दे सकता है और 50 से अधिक लोगों की जिंदगी संवार सकता है।

अंगदान का संकल्प लेना बहुत आसान है। कोई भी नागरिक भारत सरकार के 'NOTTO' पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और डोनर कार्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, संकल्प लेने के बाद अपने परिवार के सदस्यों से इस फैसले पर चर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अंतिम सहमति परिवार की ही होती है। मृत्यु के बाद शरीर के अंग मिट्टी में मिल जाते हैं या राख बन जाते हैं, लेकिन अंगदान के जरिए वे किसी अन्य की धड़कनों में, सांसों में और आंखों की रोशनी बनकर जिंदा रह सकते हैं। आइए, इस राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर हम सभी भ्रांतियों को मिटाएं और अंगदान का संकल्प लेकर किसी की जिंदगी में नया सवेरा लाएं।

भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल

नई दिल्ली, 02 अगस्त।

भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में, पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कांसुलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की योजना है।

सोशल मीडिया पर भारत–विरोधी सूचनाओं के प्रचार पर श्री दुरईस्वामी ने कहा कि चीन सरकार भी इस बारे में चिंतित है और आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दूतावास, गलत सूचनाओं से निपटने के लिए तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध करा रहा है।